ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक मेट्रो

पुराने टेंडर पर नहीं बनेगी मेट्रो, सिविल कार्यों के लिए नए सिरे से होगी प्रक्रिया

अमर उजाला ब्यूरो

ग्रेटर नोएडा। नोएडा के सेक्टर-71 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक मेट्रो के चलने में देरी हो सकती है। इसकी वजह मेट्रो के इस रूट के सिविल कार्यों के लिए ग्रेनो मेट्रो के रेट पर सहमति न बन पाना है। अब नए सिरे से टेंडर होगा। टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने में छह माह का वक्त लगेगा। फिलहाल इसका प्रस्ताव शासन में है। यूपी कैबिनेट से मंजूरी के बाद टेंडर निकलेगा।

दरअसल, सेक्टर-71 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच तेजी से बढ़ती आबादी को देखते हुए 30 दिसंबर 2020 तक मेट्रो शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया। यह भी तय हुआ कि जिस रेट पर नोएडा से ग्रेटर नोएडा मेट्रो का निर्माण हुआ है, उसी रेट में करीब 10 फीसदी वृद्धि कर इसे भी बना दिया जाए। इससे टेंडर प्रक्रिया को पूरा करने में लगने वाला समय बच जाएगा। इस रूट पर मेट्रो सेवा जल्दी शुरू हो जाएगी।

यह है योजना

नोएडा के सेक्टर-71 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नॉलेज पार्क फाइव तक मेट्रो की फिजिबिलिटी रिपोर्ट व डीपीआर पहले ही डीएमआरसी बना चुकी है। आबादी को देखते हुए इसे दो चरणों में कर दिया गया है। पहले चरण में सेक्टर 71 से ग्रेनो वेस्ट के सेक्टर दो तक मेट्रो प्रस्तावित की गई है। यह 9.155 किलोमीटर लंबा ट्रैक होगा। इसे बनाने में करीब 1521 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें ग्रेटर नोएडा को 235 करोड़ रुपये देने होंगे। बाकी रकम करीब 1286 करोड़ रुपये नोएडा और भारत सरकार से प्राप्त होगी। पहले फेज में नोएडा के सेक्टर-71 के बाद पहला स्टेशन सेक्टर-120 में बनेगा। इसके बाद सेक्टर-123, ग्रेनो वेस्ट का सेक्टर-4, सेक्टर-16 बी के बाद सेक्टर दो आखिरी स्टेशन होगा। यह भी एलिवेटेड मेट्रो होगी और सेंट्रल वर्ज पर बनेगी। इसके बाद सेकेंड फेज के मेट्रो पर काम होगा। दूसरे चरण में नॉलेज पार्क फाइव तक होगा। उसके बनने पर इस रूट की कुल लंबाई 14.958 किलोमीटर हो जाएगी।

9.155 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनेगा पहले चरण में

इस मसले पर नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और एनएमआरसी के बीच बातचीत हुई, जिसमें नोएडा-ग्रेनो मेट्रो के निर्माण की दर पर ग्रेनो वेस्ट मेट्रो बनाने पर सहमति नहीं बन सकी। सूत्र बताते हैं कि सिविल कार्यों के लिए नए टेंडर की बात कही गई है। इलेक्ट्रिक व अन्य कार्यों के लिए पुराने रेट पर काम हो सकता है। ऐसे में अब इस रूट पर काम शुरू करने से पहले टेंडर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यूपी कैबिनेट से मंजूरी के बाद यह प्रक्रिया शुरू होगी।